

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व मनन किया। यह प्रकरण प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थीगण के खातेदारी की खसरा नं. 195, 200 की भूमि में से 30 फुट का रास्ता प्राप्त करने का है व वाद के बिन्दु सं. 3 में अंकित कथन अनुसार अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के आगे चार खसरों क्रमशः 196, 197, 198 एवं 199 को संबंधित भूस्वामी द्वारा यूआईटी से आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु संपरिवर्तन करवाया गया है व उपरोक्त आवासीय कॉलोनी में मौके पर 30 फीट रास्ता दिया हुआ है जो उपरोक्त आवासीय संपरिवर्तित खसरों में से मुख्य सड़क से अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीया के खेत में आता है व अप्रार्थीगण ने खसरा संख्या 195 व 201 के बीच तारबंदी करवा कर रास्ते को बंद कर दिया अतः उक्त सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने हेतु भी यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

धारा 251 ए के अंतर्गत 2 बिन्दु मुख्यतः विचारणीय है -

1. प्रार्थीया को रास्ते की परम आवश्यकता हो केवल सुविधा के लिये नहीं एवं अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई रास्ता खसरा सं. 195, 200 में उपलब्ध नहीं है व वादी के कृषि कुआ ख.न. 213 पर पहुंच हेतु राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके पर रास्ता उपलब्ध है एवं इसी खसरे से लेकर वादीया के खसरा नं. 201, 204, 205 के बीच इनके भाईयो की कृषि भूमि है जिससे होकर वर्तमान में आवागमन किया जाता है। अतः प्रार्थीया सरलता/सुगमता हेतु धारा 251 ए के अंतर्गत रास्ता प्राप्त नहीं कर सकती।

2. प्रार्थीया के वाद बिन्दु 3 के अनुसार यह प्रार्थना पत्र सार्वजनिक रास्ते को खुलवाने हेतु पेश किया गया है। चूंकि बंद रास्ते को खुलवाने की अधिकारिता तहसीलदार को है जिसके लिये धारा 251 के अंतर्गत प्रार्थीया सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



29.7.22
(कनिष्क कटारिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबू-आबूपर्वत